



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

No. 269]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 2008/वैशाख 24, 1930

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 2008/VAISAKHA 24, 1930

गृह मंत्रालय

(सीएस प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2008

**सा.का.नि. 376(अ).**—बंदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध कम्बोडिया शाही सरकार पर लागू होंगे तथा भारत गणराज्य की सरकार और कम्बोडिया शाही सरकार के बीच हुए करार को निम्न प्रकार अधिसूचित करती है :

दण्डित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में कम्बोडिया शाही सरकार तथा भारत गणराज्य सरकार के बीच करार

कम्बोडिया शाही सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकारी देश कहा गया है;

दण्डित व्यक्तियों का उनके स्वयं के देशों में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की अभिलाषा से ; तथा यह मानते हुए कि यह उद्देश्य कोई दंडनीय अपराध करने वाले विदेशियों जिन्हें दोषसिद्ध और दंडित किया गया है, को अपने स्वयं के समाज में अपनी सजा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

निम्न प्रकार सहमत हो गई हैं :

**अनुच्छेद 1**

**परिभाषा**

इस करार के प्रयोजन के लिए :

- (क) "निर्णय" से तात्पर्य किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के उस निर्णय अथवा आदेश से है जिसके तहत दण्ड दिया गया हो;
- (ख) "प्राप्तकर्ता देश" से तात्पर्य उस देश से है जिसको दंडित व्यक्ति को सजा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जाएगा अथवा अंतरित किया गया हो;
- (ग) "दण्ड" से तात्पर्य किसी दंडनीय अपराध के लिए किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा आदेशित किसी सीमित समयावधि के लिए या जीवनपर्यंत आजादी से वंचित रखे जाने का उपाय या कोई दंड है ;
- (घ) "दण्डित व्यक्ति" से तात्पर्य संविदाकारी देशों में तत्समय प्रवृत्त कानून के अंतर्गत स्थापित न्यायालय सहित किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के तहत कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति से है;
- (ङ) "अंतरणकर्ता देश" से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दंड दिया गया हो जिसे अंतरित किया जाएगा या जिसे अंतरित कर दिया गया हो।

## अनुच्छेद 2

### सामान्य दायित्व

1. इस करार के प्रावधानों के अनुसार एक संविदाकार देश के भू-भाग में दंडित व्यक्ति को सजा काटने के लिए दूसरे संविदाकार देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है ताकि वह उसे दी गई सजा काट सके। इस संबंध में दंडित व्यक्ति इस करार के अंतर्गत अन्तरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश से ऐसे अंतरण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।
2. संविदाकार देश के कानून के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी संविदाकार देश का नागरिक हो अथवा उसकी ओर से कार्यवाई करने के लिए पात्र किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संविदाकार देश को आवेदन प्रस्तुत करके तथा उस संविदाकार देश की सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से अंतरण का अनुरोध किया जा सकता है।

## अनुच्छेद 3

### अन्तरण की शर्तें

1. इस करार के अंतर्गत किसी दंडित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अंतरित किया जाए:
  - (क) वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक हो;
  - (ख) दंडित व्यक्ति को मृत्युदण्ड न दिया गया हो;

- (ग) निर्णय अन्तिम हो;
- (घ) दंडित व्यक्ति के खिलाफ अन्तरणकर्ता देश में कोई जाँच, विचारण अथवा कोई अन्य कार्यवाही लम्बित न हो;
- (ङ) अन्तरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय दण्डित व्यक्ति की कम से कम छह माह की सजा शेष रहे गई हो अथवा उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई हो अथवा सजा असीमित समयावधि के लिए हो;
- (च) यह कि वह कृत्य या चूकें जिनके लिए उस व्यक्ति को अन्तरणकर्ता देश में दंड दिया गया ऐसे हैं जो प्राप्तकर्ता देश में भी अपराध के रूप में दण्डनीय है, अथवा यदि उनके भू-भाग में वह अपराध किया जाता तो उसे दंडनीय अपराध माना जाता।
- (छ) दंडित व्यक्ति को सैन्य कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है;
- (ज) प्राप्तकर्ता देश में दंडित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से अन्तरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो;
- (झ) दंडित व्यक्ति द्वारा अंतरण की सहमति अथवा किसी भी संविदाकार देश द्वारा दंडित व्यक्ति की आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर जरूरी समझे जाने पर संविदाकार देश के कानून के अनुसरण में उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति; और
- (ञ) अन्तरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हों।
2. अपवादिक मामलों में, यदि दंडित व्यक्ति द्वारा भोगे जा रहे दंड की शेष अवधि छह माह से कम हो तो भी अन्तरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध आपस में सहमत हो सकते हैं।

### अनुच्छेद 4

#### सूचना भेजने का दायित्व

1. यदि दंडित व्यक्ति ने दंड देने वाले देश को इस करार के तहत अंतरित किए जाने की इच्छा जाहिर की है तो, अन्तरणकर्ता देश निर्णय को प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना एवं दस्तावेज भेजेगा, जब तक कि प्राप्तकर्ता देश अथवा अन्तरणकर्ता देश ने पहले ही यह निर्णय नहीं लिया हो कि यह अन्तरण के लिए सहमत नहीं होगा :-

- (क) दंडित व्यक्ति का नाम, राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान;

- (ख) प्राप्तकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो;
- (ग) उन तथ्यों का विवरण जिन पर दंड आधारित था;
- (घ) दंड की प्रकृति, समयावधि एवं प्रारंभ होने की तारीख;
- (ङ) निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा कानून के उन संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अंतर्गत दंडित व्यक्ति के खिलाफ दंड पारित किया गया हो;
- (च) दंडित व्यक्ति के बारे में कोई चिकित्सीय, सामाजिक अथवा कोई अन्य रिपोर्ट, जहां वह उसके आवेदन के निपटान अथवा उसके कारावास के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए यह उपयुक्त हो;
- (छ) कोई अन्य जानकारी जिसके लिए प्राप्तकर्ता देश सभी मामलों में यथापेक्षित यह विनिर्दिष्ट करे कि यह उसके अंतरण की संभावना पर विचार करने के लिए जरूरी है और जिससे वह अपने कानून के अंतर्गत दंडित व्यक्ति को उसके अंतरण के सम्पूर्ण परिणामों की जानकारी देने में सक्षम हो सके ;
- (ज) अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्ति अथवा अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसरण में उसकी ओर से कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति का अनुरोध;
- (झ) किसी विचारण पूर्व नजरबंदी, क्षमा या दंड प्रवर्तन के लिए संगत किसी अन्य तथ्य को शामिल करते हुए एक विवरण पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कितना दंड पहले से ही दिया जा चुका है।

2. इस करार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज भेजेगा बशर्ते कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश ने पहले ही यह निश्चय कर लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं होगा:

- (क) एक विवरण या दस्तावेज जिसमें यह उल्लेख हो कि दंडित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक है;
- (ख) प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून की एक प्रति जिसमें उन कृत्यों या चूकों को शामिल किया गया हो जिसके कारण अंतरणकर्ता देश में दंड पारित किया गया हो तथा वह माना गया हो कि ऐसे कृत्य अथवा चूकें प्राप्तकर्ता देश के कानून के तहत अपराध हैं अथवा यदि ये उसके भू-भाग में किए जाते तो उन्हें अपराध माना जाएगा;
- (ग) दंडित व्यक्ति के अंतरण के बाद प्राप्तकर्ता देश में दंड की अवधि और प्रवर्तन से संबंधित किसी कानून अथवा विनियम का विवरण और साथ में, यदि लागू हो, उसके अंतरण के संबंध में इस करार के अनुच्छेद 8 के पैरा 2 के प्रभाव का विवरण;

- (घ) दंडित व्यक्ति का अंतरण स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता देश की स्वीकृति और दंडित व्यक्ति के शेष बचे दंड का प्रबंध करने संबंधी अनुबंध; और
- (ङ) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज जिसे अंतरणकर्ता देश जरूरी समझे।

### अनुच्छेद 5

#### अनुरोध एवं उत्तर

1. अंतरण संबंधी अनुरोध लिखित रूप से निर्धारित प्रोफार्मा, यदि कोई हो, में किए जाएंगे तथा ये राजनयिक चैनलों के माध्यम से अंतरणकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्तकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकरण को संबोधित होंगे। इन अनुरोधों के उत्तर इन्हीं चैनलों के माध्यमों से दिए जाएंगे।
2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के प्रयोजनार्थ, भारत के संबंध में केन्द्रीय प्राधिकारी “गृह मंत्रालय” और कम्बोडिया के संबंध में ‘मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, किंगडम ऑफ कम्बोडिया, नाम पेन होगा।
3. प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को तत्काल अपने इस निर्णय से तत्परता से अवगत कराएगा कि वह इस अंतरण के अनुरोध से सहमत है अथवा नहीं।

### अनुच्छेद 6

#### सहमति तथा उसका सत्यापन

1. अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 3 के पैरा 1 (झ) के अनुसरण में अंतरण की सहमति देने वाला व्यक्ति ऐसी सहमति स्वेच्छापूर्वक और उसके विधिक परिणामों की पूरी जानकारी के साथ दे रहा है। ऐसी सहमति देने की प्रक्रिया अंतरणकर्ता देश के कानून से अधिशसित होगी।
2. अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को यह सत्यापित करने का अवसर देगा कि सहमति इस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्धारित शर्तों के अनुसार दी गई है।

### अनुच्छेद 7

#### प्राप्तकर्ता देश के लिए अंतरण का प्रभाव

1. प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी इस संधि के अनुच्छेद 8 में दी गई शर्तों के तहत किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश के जरिए, जैसा भी उसके राष्ट्रीय कानून के तहत अपेक्षित हो, दंड का प्रवर्तन जारी रखेगा।

2. इस संधि के अनुच्छेद 10 के उपबंधों के अधीन दंड का प्रवर्तन प्राप्तकर्ता देश के कानून द्वारा नियंत्रित होगा और केवल वही देश इस संबंध में सभी उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

### अनुच्छेद 8

#### दंड का सतत् प्रवर्तन

1. प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश द्वारा यथानिर्धारित सजा के कानूनी स्वरूप और अवधि से बाध्य होगा।
2. तथापि, यदि दिया गया दंड अपने स्वरूप अथवा अवधि अथवा दोनों ही दृष्टियों से प्राप्तकर्ता देश के कानून से असंगत हो अथवा उसके कानून में ऐसा अपेक्षित हो तो वह देश न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा दंड को अपने स्वयं के कानून द्वारा निर्धारित सजा अथवा उपाय में परिवर्तित कर सकता है। जहां तक इसके स्वरूप तथा अवधि का संबंध है, सजा अथवा उपाय यथासंभव अंतरणकर्ता देश के फैसले में दी गई सजा के संगत होने चाहिए। तथापि, यह अंतरणकर्ता देश में दी गई सजा के स्वरूप अथवा अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

### अनुच्छेद 9

#### अंतरणकर्ता देश पर दंड पूरा होने का प्रभाव

जब प्राप्तकर्ता देश इस संधि के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 1(क) के तहत अंतरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि दंड पूरा हो गया है तो ऐसी अधिसूचना का प्रभाव अंतरणकर्ता देश में उस दंड का पूरा होना माना जाएगा।

### अनुच्छेद 10

#### माफी, राजक्षमा अथवा लघुकरण तथा निर्णय की पुनरीक्षा

1. केवल अंतरणकर्ता देश ही निर्णय की समीक्षा के लिए किसी आवेदन-पत्र पर निर्णय लेगा।
2. कोई भी संविदाकारी देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुरूप दंड की माफी, राजक्षमा प्रदान कर सकेगा अथवा दंड का लघुकरण कर सकेगा।

### अनुच्छेद 11

#### दंड के प्रवर्तन की समाप्ति

जैसे ही अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी भी ऐसे फैसले अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दंड का प्रवर्तन समाप्त किया गया हो, तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।

**अनुच्छेद 12****दंड के प्रवर्तन संबंधी सूचना**

1. प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगा:
  - (क) जब दंड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो; अथवा
  - (ख) "यदि दंड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले दंडित व्यक्ति हिरासत से भाग जाता है तब ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता देश को चाहिए कि वह कैदी की गिरफ्तारी हेतु हर-सम्भव प्रयास करे ताकि वह अपनी शेष दंड पूरी कर सके और उस कैदी को प्राप्तकर्ता देश के कैदी के भागने संबंधी कानून के अंतर्गत अपराध के लिए अभियोजित किया जा सके।
2. यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा अपेक्षित हो तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

**अनुच्छेद 13****अभिवहन**

यदि कोई भी संविदाकारी देश दंडित व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है तो दूसरा संविदाकारी देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भूभाग से अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्तियों के अभिवहन को सुकर बनाने में सहयोग करेगा लेकिन वह किसी ऐसे दंडित व्यक्ति के अभिवहन से मना कर सकता है जो स्वयं उसका एक राष्ट्रिक हो। ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश को ऐसे अभिवहन के बारे में अग्रिम नोटिस देगा।

**अनुच्छेद 14****लागत**

अंतरणकर्ता देश के अनन्य भू-भाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर, इस करार को लागू करने में आने वाले सभी व्यय प्राप्तकर्ता देश द्वारा वहन किए जाएंगे। तथापि, प्राप्तकर्ता देश अंतरण में होने वाले व्यय की संपूर्ण अथवा आंशिक वसूली दंडित व्यक्ति अथवा किसी अन्य साधन से कर सकता है।

**अनुच्छेद 15****भू-भागीय अनुप्रयोग**

1. यह करार निम्न पर लागू होगा:
  - (क) भारत गणराज्य तथा
  - (ख) कम्बोडिया की शाही सरकार पर

संविदाकार देश के भू-भाग के संदर्भ में भू-भाग का निवर्चन तदनुसार किया जाएगा।

2. किसी ऐसे भू-भाग, जिसमें इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार विस्तार किया गया है, में इस करार के अनुप्रयोग को किसी भी संविदाकारी देश द्वारा दूसरे संविदाकारी देश को राजनयिक चैनलों के माध्यम से दिए गए छः माह के नोटिस की अवधि के खत्म होने पर समाप्त किया जा सकता है।

### अनुच्छेद 16

#### भाषा

1. अनुरोध एवं सहायक दस्तावेजों के साथ अनुरोधकर्ता देश की भाषा अथवा किसी एक राजभाषा में अनूदित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।

### अनुच्छेद 17

#### लागू होने का दायरा

यह करार इसके प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दंड के प्रवर्तन पर लागू होगा।

### अनुच्छेद 18

#### संशोधन

इस करार में किसी भी प्रकार के संशोधन अथवा परिवर्तन जिन पर संविदाकार देशों ने अपनी सहमति प्रकट कर दी है, उस समय लागू होंगे जब राजनयिक नोट्स के पारस्परिक आदान प्रदान के माध्यम से इसकी पुष्टि की जाएगी।

### अनुच्छेद 19

#### अंतिम प्रावधान

1. यह करार, अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा तथा अनुसमर्थन के लिखित दस्तावेजों के परस्पर विनिमय की तारीख से लागू होगा।
2. यह करार उस तारीख से छः माह तक लागू रहेगा जिस तारीख को कोई भी संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश को इसे समाप्त करने के बारे में लिखित सूचना देगा।
3. किसी भी परिसमापन के बावजूद यह करार उस दंडित व्यक्ति के दंडों के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिसे इस परिसमापन के लागू होने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत अंतरित किया गया हो।



इस संधि के साक्ष्य के रूप में अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इस संबंध में उचित प्रकार से प्राधिकृत किए जाने पर अधोहस्ताक्षरी ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित होने के नाते इसे नई दिल्ली में दिनांक 8 दिसम्बर, 2007 को हिन्दी, खमेर तथा अंग्रेजी भाषा की दो प्रतियों में तैयार किया गया है। यदि कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से  
शिवराज वि. पाटील  
गृह मंत्री

कम्बोडिया की शाही सरकार  
की ओर से

होर नामहोंग  
उप प्रधानमंत्री और विदेश तथा  
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री

[फा. सं. V-17011/3/2005-पीआर]

निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CS Division)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2008

**G.S.R. 376(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Kingdom of Cambodia and notifies the agreement entered into between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom Cambodia as under :

### AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA AND THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

The Government of the Republic of India and the Royal Government of Cambodia hereinafter referred to as the Contracting States;

**Desiring** to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and

**Considering** that this objective should be fulfilled by giving foreigners, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences within their own society;

**Have agreed** as follows:

## **ARTICLE 1**

### **Definitions**

For the purpose of this Agreement:

- (a) “Judgement” means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b) “receiving State” means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence;
- (c) “sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time or for life imprisonment on account of a criminal offence;
- (d) “sentenced person” means a person undergoing a sentence of imprisonment under an order passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the Contracting States;
- (e) “transferring State” means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

## **ARTICLE 2**

### **General Obligations**

1. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the transferring State or the receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.

2. Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State by making an application to the Contracting State and in the manner prescribed by the Government of that Contracting State.

### ARTICLE 3

#### Conditions for transfer

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:

- (a) the person is a national of the receiving State;
- (b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
- (c) the judgment is final;
- (d) no inquiry, trial or any other proceeding is pending against the sentenced person in the transferring State;
- (e) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment or the sentence is indeterminate;
- (f) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring State are those which are punishable as a crime in the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (g) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;
- (h) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other interest of the transferring State;
- (i) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State; and
- (j) the transferring and receiving States agree to the transfer.

2. In exceptional cases, the transferring and receiving States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months.

## ARTICLE 4

### Obligation to furnish information

1. If the sentenced person has expressed an interest to the sentencing State in being transferred under this Agreement, the transferring State shall send the following information and documents to the receiving State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person;
- (b) his address, if any, in the receiving State;
- (c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
- (d) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
- (e) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
- (f) a medical, social or any other report on the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;
- (g) any other information which the receiving State may specify as required in all cases to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him under its law;
- (h) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the transferring State; and

- (i) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence.
2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the receiving State shall send the following information and documents to the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
- (a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving State;
  - (b) a copy of the relevant law of the receiving State constituting the acts or omissions, on account of which the sentence has been passed in the transferring State, as if such acts or omissions were an offence under the law of the receiving State or would constitute an offence if committed on its territory;
  - (c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 8 of this Agreement on his transfer;
  - (d) the willingness of the receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
  - (e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.

## ARTICLE 5

### Requests and replies

1. Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and addressed through the central authority of the transferring State through diplomatic channels to the central Authority of the receiving State. Replies shall be communicated through the same channels.

2. For the purpose of paragraph 1 of this Article, the Central Authority shall be, in relation to India, the Ministry of Home Affairs; and in relation to Cambodia, shall be the Ministry of Interior, Kingdom of Cambodia, Phnom Penh.
3. The receiving State shall promptly inform the transferring State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

## **ARTICLE 6**

### **Consent and its verification**

1. The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1(i) of Article 3 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the transferring State.
2. The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

## **ARTICLE 7**

### **Effect of transfer for the receiving State**

1. The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 8 of this Agreement.
2. Subject to the provisions of Article 10 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

## **ARTICLE 8**

### **Continued enforcement of sentence**

1. The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the transferring State.
2. If, however, the sentence is by its nature or duration or both incompatible with the law of the receiving State, or its law so requires, that State may, by

court or administrative order, adapt the sentence to a punishment or measure prescribed by its own law. As to its nature and duration the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the transferring State. It shall however not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the transferring State.

## **ARTICLE 9**

### **Effect of completion of sentence for the transferring State**

When the receiving State notifies the transferring State under paragraph 1(a) of Article 12 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging that sentence in the transferring State.

## **ARTICLE 10**

### **Pardon, amnesty or commutation and review of judgment**

- (1) The transferring State alone shall decide on any application for the review of the judgement.
- (2) Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.

## **ARTICLE 11**

### **Termination of enforcement of sentence**

The receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

## **ARTICLE 12**

### **Information on enforcement of sentence**

1. The receiving State shall notify the transferring State:
  - (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
  - (b) If the sentenced person escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed, in such cases the receiving State

shall make every effort to have the prisoner arrested so that he serves the remainder of his sentence and that the prisoner be prosecuted for committing an offence under the relevant law of the receiving State on escape of prisoner.

2. The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the transferring State.

### ARTICLE 13

#### Transit

If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit to any sentenced person who is one of its own nationals. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.

### ARTICLE 14

#### Costs

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State. The receiving State may, however, seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source.

### ARTICLE 15

#### TERRITORIAL APPLICATION

1. This agreement shall apply:
  - (a) to the Republic of India, and
  - (b) to the Kingdom of Cambodia

and reference to the territory of a Contracting State shall be construed accordingly.

2. The application of this agreement to any territory, in respect of which extension has been made in accordance with paragraph 1 of this Article, may be terminated upon expiry of six months notice given by either Contracting State to the other through the diplomatic channels.



**ARTICLE 16****Language**

Requests and supporting documents shall be accompanied by a translation into the language or one of the official language of the requesting State or English.

**ARTICLE 17****Scope of application**

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after its entry into force.

**ARTICLE 18****Amendments**

Any amendments or modifications to this Agreement agreed by the Contracting States shall come into effect when confirmed by an Exchange of Diplomatic Notes.

**ARTICLE 19****Final provisions**

1. This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date on which instruments of ratification are exchanged.
2. The Agreement shall continue to remain in force until six months from the date upon which either Contracting State gives written notice to the other Contracting State of its intention to terminate it.
3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the sentenced persons who have been transferred under this agreement before the date on which such termination takes effect.

**In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.**

**Done in duplicate at New Delhi on the 8<sup>th</sup> day of December 2007 in the Hindi, Khmer and English languages, all texts being equally authentic. In case of difference in interpretation the English text shall prevail**

**For the Government of the  
Republic of India**

**For the Government of the  
Kingdom of Cambodia**

**Shivraj V. Patil  
Home Minister**

**HOR Namhong  
Deputy Prime Minister and  
Minister of Foreign Affairs and  
International Cooperation**

[F. No. V-17011/3/2005-PR]

NIRMALJEET SINGH KALSI, Jt. Secy.